



2026:AHC:56094

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 10879/2026

मैसर्स जे.वी. एंड कंपनी, गोपाल मोहल्ला, चंदौसी, द्वारिका प्रसाद के माध्यम सेआवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....विपक्षी पक्ष (गण)

आवेदक के अधिवक्ता : संतोष कुमार गुप्ता

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 73

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. यह त्वरित आवेदन शिकायत संख्या 297/2022 (विनोद कुमार गोयल बनाम मैसर्स जे.वी. एंड कंपनी, प्रोपराइटर द्वारिका प्रसाद के माध्यम से) धारा 138 एन.आई. एक्ट की पूरी कार्यवाही को रद्द करने, तथा सिविल जज (जे.डी.)/जे.एम. संभल, चंदौसी द्वारा पारित समन आदेश दिनांक 14.09.2022 और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संभल, चंदौसी द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 37/2025 में पारित आदेश दिनांक 14.11.2025 को चुनौती देने के लिए दायर किया गया है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने दलील दी कि वर्तमान शिकायत विपक्षी संख्या 2 के पति द्वारा दायर की गई थी, लेकिन इस आवेदन के लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण विपक्षी संख्या 2 से 5 को उत्तराधिकारियों के रूप में पक्षकार बनाया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. शिकायत में आरोप है कि आवेदक ने 29.07.2022 को 20 लाख रुपये का चेक जारी किया था, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित हो गया। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने नोटिस जारी किया और ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों की जांच के बाद समन जारी किया। आवेदक ने इस आदेश को पुनरीक्षण के माध्यम से चुनौती दी, जिसे अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रोपराइटरशिप फर्म को 'ज्यूरिस्टिक पर्सन' (विधिक व्यक्ति) नहीं माना जा सकता।
5. विद्वान ए.जी.ए. ने कार्यवाही रद्द करने की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया और तर्क दिया कि आदेश में कोई अवैधता नहीं है। प्रथम दृष्टया, आवेदक एक प्रोपराइटरशिप है, कोई विधिक व्यक्ति नहीं, इसलिए अलग से नोटिस की आवश्यकता नहीं थी।
6. विवादित आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों को देखने के बाद ही आदेश पारित किया है। आदेश उचित है और इसमें कोई अवैधता नहीं है। फर्म को उसके प्रोपराइटर द्वारिका प्रसाद के माध्यम से पक्षकार बनाया गया है। आवेदक द्वारा उठाए गए तर्कों की इस चरण पर जांच नहीं की जा सकती।
7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्री ओम सेल्स बनाम अभय कुमार @ अभय पटेल और अन्य (2025 एससीसी आनलाइन एससी 2897) के मामले में निम्नलिखित निर्णयों पर विचार किया है:

14. मारुति उद्योग लिमिटेड बनाम नरेंद्र और अन्य में, इस न्यायालय ने यह माना कि यह धारणा बनाई जानी चाहिए कि चेक धारक को धारा 138 में संदर्भित प्रकृति का चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के निर्वहन के लिए प्राप्त हुआ है, जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए और, इसलिए, कार्यवाही के प्रारंभिक चरण में आरोपी की दलील को स्वीकार करना और शिकायत को रद्द करना उच्च न्यायालय के लिए उचित नहीं था।

15. इसी तरह, रंगप्पा बनाम श्री मोहन में, यह माना गया कि एन.आई. एक्ट की धारा 139 द्वारा अनिवार्य धारणा में कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व का अस्तित्व शामिल है। यह देखा गया कि ऐसी धारणा खंडन योग्य है, और आरोपी को मुकदमे के दौरान अपना बचाव प्रस्तुत करना चाहिए।

16. राजेशभाई मूलजीभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य में, यह माना गया कि उच्च न्यायालय को एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत आपराधिक शिकायत को इस आधार पर रद्द नहीं करना

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चाहिए कि प्रश्नगत चेक ऋण या दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया था या नहीं, क्योंकि यह तथ्य का विवादित प्रश्न है। विशेष रूप से तब, जब एन.आई. एक्ट की धारा 139 चेक जारी करने के संबंध में एक वैधानिक धारणा उत्पन्न करती है।

17. रतीश बाबू उन्नीकृष्णन बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) में, इस न्यायालय ने माना कि जब एन.आई. एक्ट की धारा 139 के तहत कानूनी धारणा मौजूद हो, तो शिकायत रद्द करने के लिए मुकदमे से पूर्व चरण में तथ्य के विवादित प्रश्न पर विस्तृत जांच करना विवेकपूर्ण नहीं होगा। निर्णय के प्रासंगिक अवलोकन नीचे उद्धृत हैं:

"17. ऊपर निर्धारित कानून का प्रस्ताव यह पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि अदालत को मुकदमे से पूर्व चरण में शिकायत रद्द करने की राहत देने में धीमी गति अपनानी चाहिए, विशेष रूप से इस मामले की तरह कानूनी धारणा के कारण। यह भी ध्यान देने योग्य है कि बिना किसी सबूत के पेश किए गए तथ्यात्मक बचाव की गुणवत्ता ऐसी होनी चाहिए जिसे झुठलाया न जा सके, ताकि शिकायत में लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से गलत साबित किया जा सके।"

"18. मुकदमे से पूर्व चरण में आपराधिक प्रक्रिया को रोकने के परिणाम गंभीर और अपूरणीय हो सकते हैं। प्रारंभिक चरणों में कार्यवाही रद्द करने का परिणाम पक्षों को सबूत पेश करने का अवसर दिए बिना अंतिम निर्णय के रूप में होगा और इसका परिणाम यह होगा कि उचित मंच, यानी ट्रायल कोर्ट, भौतिक साक्ष्यों को तौलने से बाहर हो जाएगा। यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो आरोपी को आपराधिक प्रक्रिया में अनुचित लाभ मिल सकता है। इसके अलावा, कानूनी धारणा के कारण, जब अपीलकर्ता द्वारा चेक और हस्ताक्षर पर विवाद नहीं किया जाता है, तो इस स्तर पर सुविधा का संतुलन शिकायतकर्ता/अभियोजन के पक्ष में होता है, क्योंकि आरोपी के पास मुकदमे के दौरान धारणा का खंडन करने के लिए बचाव साक्ष्य पेश करने का अवसर होगा।"

"19. ऐसी स्थिति में, समन आदेश के स्तर पर शिकायतकर्ता को अदालत से बाहर करना, जबकि तथ्यात्मक विवाद पर अभी ट्रायल कोर्ट द्वारा विचार किया जाना बाकी है, हमारी राय में विवेकपूर्ण नहीं होगा। प्रथम दृष्टया धारणा के आधार पर, यहाँ आपराधिकता के तत्व

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। इसलिए, जब कार्यवाही प्रारंभिक चरण में हो, तो आपराधिक प्रक्रिया को रोकना उचित नहीं है।”

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त मामले का निर्णय करते समय पैराग्राफ 13 और 18 में यह देखा है कि:

“13. हालांकि, उच्च न्यायालय ने धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में यह परीक्षण करना शुरू कर दिया कि क्या चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए जारी किया गया था। हमारी राय में, ऐसा अभ्यास अनुचित था क्योंकि एन.आई. एक्ट की धारा 139 के तहत, यह धारणा है कि चेक के धारक को ऋण या दायित्व के निर्वहन के लिए चेक प्राप्त हुआ है। इस धारणा को मुकदमे में साक्ष्यों द्वारा झुठलाया जा सकता है। यह मुद्दा उचित रूप से या तो मुकदमे में, या बाद में अपील/पुनरीक्षण अदालत द्वारा तय किया जा सकता है।”

“18. इस न्यायालय के उक्त निर्णयों और एन.आई. एक्ट की धारा 139 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने मुकदमे से पूर्व चरण में चेक जारी करने के संबंध में ‘रोविंग इंकवायरी’ (विस्तृत छानबीन) करके गलती की है। धारा 482 के तहत शक्ति के प्रयोग में ऐसा अभ्यास उचित नहीं था, विशेष रूप से जब शिकायत के आरोपों से पता चलता था कि चेक दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया था। चूंकि शिकायत के आरोपों से धारा 138 एन.आई. एक्ट की आवश्यक सामग्री प्रथम दृष्टया पूरी होती है, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमे से पहले न तो समन आदेश और न ही शिकायत को रद्द किया जा सकता था।”

9. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन खारिज किया जाता है।

18 मार्च, 2026

मीनु सिंह

(दीपक वर्मा, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।